24 जनवरी 2018

जापान-चीन संबंध: एक नई गतिकी

*डॉ जोजिन वी. जॉन**

2017 की दूसरी छमाही के दौरान , जापान-चीन संबंध में तेजी देखी गई । संबंधों में सुधार से शीर्षस्तरीय नेतृत्व की बैठकों और उच्चस्तरीय राजनीतिक और व्यापारिक आदान-प्रदान में वृद्धि हुई। द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति उच्चतम स्तर पर रही जब 11 नवंबर, 2017 को "ताजा शुरुआत" के रूप में दनांग में हुई अपनी बैठक के बारे में प्रधानमंत्री शिंजो आबे और राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने संयुक्त रूप से दुनिया को बताया। यह बयान एक प्रमाण है प्रधानमंत्री आबे और राष्ट्रपति शी द्वारा बेहतर द्विपक्षीय संबंधों को दी गयी प्राथमिकता को दर्शाने का, इस सन्दर्भ में कि दोनों नेताओं ने अपने-अपने राजनीतिक आधार को अगले पांच वर्षों के लिए सुरक्षित कर लिया है। जापान-चीन संबंधों में नई गतिशीलता की एक प्रमुख वि शेषता चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) के प्रति टोक्यो का परिवर्तित रुख है, जो 'उदासीनता' से 'समर्थन' की ओर बदल गया है। नवीनतम जापान-चीन शिखर सम्मेलन और बीआरआई के लिए जापान के बदलते दृष्टिकोण का विश्लेषण करते हुए , यह आ लेख जापान-चीन संबंध की नई गतिशी लता की व्याख्या करता है।

जापान-चीन शिखर सम्मेलन

11 नवंबर, 2017 को प्रधानमंत्री आबे और राष्ट्रपति शी ने वियतनाम के दनांग में एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग (एपीईसी) शिखर सम्मेलन के मौके पर मुलाकात की। यह बैठक दोनों नेताओं के बीच पांचवीं शिखर बैठक थी। दनांग की तरह, पिछली सभी बैठकें अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक कार्यक्रमों के आयोजन पर ही हुई थीं। पिछले पांच वर्षों से सत्ता में होने के बावजूद , दोनों नेताओं को आधिकारिक दौरा करना बाकी है।

शिखर सम्मेलन के बाद, प्रधानमंत्री आबे ने कहा "राष्ट्रपति शी ने कहा कि यह बैठक जापान और चीन के बीच संबंधों की एक नई शुरुआत है। मैं भी पूरी तरह से ऐसा ही सोचता हूं।"[1] दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि "चीन-जापान संबंधों का स्थाई विकास" दोनों देशों के हित में है। उन्होंने 2017 में जापान और चीन के बी च राजनयिक संबंधों के सामान्य बनने की 45वीं वर्षगांठ और 2018 में शांति और मित्रता की संधि के समापन की 40वीं वर्षगांठ के मौके पर द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर आधारों पर बनाए रखने पर सहमति व्यक्त की। दोनों नेताओं ने माना कि द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने में आर्थिक संबंधों को विकसित करना "सबसे महत्वपूर्ण नींव" में से एक है। इस दिशा में, दोनों नेताओं ने वित्त, खाद्य व्यापार, पर्यावरण और ऊर्जा संरक्षण, पर्यटन तथा घटती जन्मदर व बूढ़ी होती जनसंख्या सहित अन्य क्षेत्रों में आगे सहयोग को बढ़ावा देने पर सहमति जताई।[2]

राष्ट्रपति शी के साथ शिखर सम्मेलन के दो दिन बाद, प्रधानमंत्री आबे ने मनीला में आसियान क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन में चीनी प्रीमियर ली केकियांग से भी मुलाकात की। बैठक के बाद, प्रीमियर ली ने कहा "बेशक, हम कुछ संवेदनशील कारकों के अस्तित्व से इनकार नहीं कर सकते ... मुझे लगता है कि दोनों पक्षों को चीन-जापान संबंधों में सुधार की गति को ठोस स्वरूप प्रदान करने के लिए मिलकर कड़ी मेहनत करनी चाहिए।"

एक सकारात्मक टिप्पणी पर, प्रधानमंत्री आबे ने जवाब दिया, "मैं चाहता हूं कि हम रणनीतिक, पारस्परिक रूप से लाभप्रद संबंधों के विकास के लिए दृढ़ता से आगे बढ़ाएं।"[3] प्रधानमंत्री आबे और प्राइमर ली के बीच बैठक द्विपक्षीय संबंधों के आर्थिक आयाम पर अधिक केंद्रित थी। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (आरसीईपी) और जापान-चीन-आरओके मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के शीघ्र निष्पादन के लिए जापान और चीन के बीच समन्व य को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की।[4]

जापानी विदेश मंत्रालय ने कहा कि शिखर सम्मेलन में, प्रधानमंत्री आबे और राष्ट्रपति शी ने अप्रत्याशित परिस्थितियों से बचने के लिए चीनी सैन्य और जापानी आत्मरक्षा बल के बीच एक संचार तंत्र के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए बात चीत को गति प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की। 6 दिसंबर, 2017 को शिखर सम्मेलन से संकेत मिलने के बाद, टोक्यो और बीजिंग "बड़े पैमाने पर एक समुद्री और हवाई संचार तंत्र को लागू करने के तरीके पर सहमत हुए"।[5] एक बार लागू कर दिए जाने के बाद यह तंत्र दोनों देशों के रक्षा अधिकारियों के बीच हॉटलाइन के रूप में काम करेगा। हॉटलाइन बनाने के पहले समझौते पर 2007 में हस्ताक्षर किया गया था। हालांकि, चर्चा 2015 तक रुकी हुई थी। 6 दिसंबर को, वे "संकट प्रबंधन हॉटलाइन के भौगोलिक दायरे को अपरिभाषित छोड़ने" पर सहमत हुए।[6] हालाँकि हाल तक, यद्यपि कि तंत्र की संरचना पर टोक्यो और बीजिंग सहमत रहे, फिर भी तंत्र के अधीन आने वाले भौगोलिक क्षेत्र को लेकर मतभेद को दूर करने में चर्चा सफल नहीं हो सकी।[7] टोक्यो का मानना था कि सेनकाकू द्वीप (दियाओयू द्वीप) के आसपास का जल और वायु क्षेत्र, जिसे वह प्रशासित करता है, तंत्र के अधीन नहीं होना चाहिए, लेकिन बीजिंग इसका विरोध कर रहा था।[8]

जापानी विदेश मंत्रालय के अनुसार, दोनों बैठकों में, जापान और चीन ने कोरियाई प्रायद्वीप में विकास को लेकर विचारों का आदान-प्रदान किया और दोनों ही पक्षों ने इस बात को दृढ़तापूर्वक माना कि कोरियाई प्रायद्वीप का परमाणु विमुक्तिकरण एक "साझा लक्ष्य" है।

शिखर सम्मेलन में , राष्ट्रपति शी के साथ प्रधानमंत्री आबे ने विचार व्यक्त किया कि "अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को उत्तर कोरिया पर अधिकतम दबाव बनाना चाहिए , और उन्होंने चीन से और कदम उठाने का अनुरोध किया।"[9] हालांकि, उत्तर कोरिया को लेकर चीन ने चुप्पी साध ली। जापान और चीन दोनों ही कोरियाई प्रायद्वीप के परमाणु विमुक्तिकरण के लक्ष्य को साझा करते हैं , लेकिन इस मुद्दे पर उनके दृष्टिकोण भिन्न हैं। जहाँ जापान संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ मिलकर "अधिकतम दबाव" की सख्त नीति का अनुसरण कर रहा है, तो दूसरी ओर, चीन राजनीतिक और कूटनीतिक माध्यम से परमाणु मुद्दे के शांतिपूर्ण समाधान की वकालत करता रहा है।

हालाँकि शिखर सम्मेलन ने जापान- चीन संबंधों में एक सकारात्मक प्रवृत्ति को जाहिर किया, फिर भी बैठक में कुछ असहज पहलुओं को भी प्रतिबिंबित किया गया। चीनी विदेश मंत्रालय के अनुसार, राष्ट्रपति शी ने जोर देकर कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए "आपसी विश्वास" महत्वपूर्ण है और उन्होंने उम्मीद जताई कि रणनीतिक सहमति को प्रतिबिंबित करने के लिए जापान "अधिक व्यावहारिक कार्रवाई करेगा और अधिक विशिष्ट नीतियों को अपनाने की दिशा में बढेगा।"

बीजिंग ने टोक्यो को "क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण को सक्रिय रूप से बढ़ावा " देकर व्यावहारिक उपायों पर ध्यान देने तथा "बेल्ट एंड रोड " के ढांचे के भीतर सहयोग को अग्रसर करने के लिए कहा।[10] बयान में यह भी कहा गया कि राष्ट्रपति शी ने प्रधानमंत्री आबे को याद दिलाया कि जापान को इतिहास और ताइवान से संबंधित मुश्किल मुद्दों को ठीक से संभालने की जरूरत है । प्रधानमंत्री आबे ने कहा कि "पूर्वी चीन सागर में स्थिरता के बिना जापान- चीन संबंधों में कोई वास्तविक सुधार नहीं होगा।" [11]

4 दिसंबर, 2017 को तीसरे जापान- चीन सीईओ शिखर सम्मेलन में दिए गए भाषण में , प्रधानमंत्री आबे ने कहा कि "जापान और चीन के बीच अविभाज्य संबंध हैं।"[12] प्रधानमंत्री आबे ने राष्ट्रपति शी और प्रीमियर ली के साथ अप ने शिखर सम्मेलन की तुलना 45 वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री काकूई तनाका की अध्यक्ष माओत्से तुंग और प्रीमियर झोउ एनलाई के साथ हुई शिखर बैठक से की जिसके कारण जापान-चीन संबंध सामान्य हुए थे। द्विपक्षीय संबंधों में एक नए युग की शुरुआत का संकेत देते हुए उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रपति शी के साथ उनकी मुलाकात "वास्तव में जापान-चीन संबंधों के लिए एक नई शुरुआत है।"

मीडिया की प्रतिक्रिया

जापानी मीडिया ने, सामान्य तौर पर, प्रधानमंत्री आबे की बैठकों को राष्ट्रपति शी और प्रीमियर ली के साथ जापान और चीन के संबंधों में सु धार के संकेत के रूप में दे खा और द्विपक्षीय संबंधों को सकारात्मक पथ पर और गति देने में सफल रहा। जापानी मीडिया ने राजनीतिक परिक्षेत्र के परे

जाकर क्षेत्रीय स्थिरता के लिए जापान-चीन संबंधों में सुधार की आवश्यकता को चिह्नित किया। इस दिशा में, उन्होंने शीर्ष स्तर के राजनीतिक आदान-प्रदानों को फिर से शुरू करने का आग्रह किया , जो पिछले पांच वर्षों से रुके हुए थे। जापानी समाचार पत्र *मेनिची शिम्बुन* ने अपने संपादकीय में दनांग में हुई आबे-शी शिखर सम्मेलन को अतीत के द्विपक्षीय शिखर सम्मेलनों की तुलना में "अत्यधिक परिवर्तित" की संज्ञा दी।[13] यह देखा गया कि शिखर सम्मेलन में दोनों नेताओं ने "दोस्ती के रुख को सजीव रूप में सामने रखा" और प्रधानमंत्री आबे के साथ राष्ट्रपति शी ने मुस्कुराते हुए हाथ मिलाया।

वामपंथी झुकाव वाले *असाहि शिम्बुन* ने राष्ट्रपति शी की "ताज़ा शुरुआत" वाली टिप्पणी को शिखर सम्मेलन के अपने विवरण के रूप में दोहराया। अखबार ने दोनों नेताओं से आग्रह किया कि घरेलू मोर्चे पर उनकी बढ़ी हुई ताकत के बल पर जो अवसर उत्पन्न हुआ है उसका लाभ उठाकर वे एक-दूसरे के राज्यों का आधिकारिक दौरा कर लम्बे समय से चली आ रही कड़ुवाहट को दूर करें । संपादकीय में जापा न से "स्वतंत्र और खुले इंडो- पैसिफिक" रणनीति को "बेल्ट एंड रोड " पहल के प्रतिद्वंद्वी के रूप में बढ़ावा नहीं देने का आग्रह किया गया और दोनों देशों को सुझाव दिया कि दोनों प्रस्तावों में सहयोग के लिए साझा आधार खोजने के लिए बातचीत शुरू की जाए। इसने जापान को याद दिलाया कि अमेरिका के साथ गठबंधन और अमेरिका और दक्षिण कोरिया के साथ त्रिपक्षीय सहयोग सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है लेकिन इस क्षेत्र में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए कम है।

अपने संपादकीय में, रूढ़िवादी झुकाव वाले जापानी समाचार पत्र योमुरी ने एशिया में स्थिर ता के लिए जापान और चीन से अपने मतभेदों को दूर करने में सहयोग का आग्रह किया। [15] अखबार ने तर्क दिया कि इन परियोजनाओं की पारदर्शिता और खुलेपन तथा प्रभाविता के लिए जरूरी है कि जापान चीन के बेल्ट एंड रोड पहल में "ठीक तरीके से शामिल" रहे। अखबार ने कहा कि जापानी समुद्री क्षेत्र में चीनी घुसपैठ को नजरअंदाज नहीं करना महत्वपूर्ण है और शिखर सम्मेलन में पूर्वी चीन सागर को लेकर चीन को दिए दृढ़ सन्देश के लिए प्रधानमंत्री की सराहना की।

चीन के *ग्लोबल टाइम्स* ने प्राइमर ली के साथ बैठक के बाद प्रधान मंत्री आबे के बयान का उल्लेख "चीन-जापान संबंधों पर दुर्लभ रचनात्मक बयान" के रूप में किया ।[16] अखबार ने कहा कि चीन-जापान संबंधों को लेकर हाल के दिनों में प्रधानमन्त्री आबे बहुत ही सकारात्मक रहे हैं । हालाँकि, यह टोक्यो के अनुसरण पर संदेह किए बिना नहीं था। इसने चीन के साथ संबंध सुधारने के आबे के प्रयासों के पीछे अमेरिका-चीन संबंध में तरक्की को मुख्य कारण माना । अखबार ने ये भी कहा कि चीन को नियंत्रित करने में आबे अन्य देशों को एकजुट करने में विफल रहे हैं। इसने टिप्पणी की कि सकारात्मक रुख होने के बावजूद दोनों देशों में कुछ मुद्दों पर मतभेद हैं । इसने प्रधानमंत्री आबे से चीन के साथ संबंधों में सुधार के अवसर का लाभ उठाने का आग्रह किया।

चीन के प्रति जापान का नवीन दृष्टिकोण

सेनकाकू द्वीप पर विवाद के बाद 1972 में दोनों देशों ने राजनयिक संबंध स्थापित किए थे, फिर भी 2010 की पहली छमाही के दौरान जा पान-चीन संबंध अपने निम्नतम स्तर पर थे। इस अवधि के दौरान टोक्यो और बीजिंग उच्चस्तरीय बैठकों से दूर रहे । प्रधानमंत्री आबे और राष्ट्रपति शी ने एपीईसी बैठक के मौके पर 2014 में अपना पहला शिखर सम्मेलन किया। तब से हर साल शिखर

बैठक और विदेश मंत्री स्तर की बैठकें आयोजित की जाती र ही हैं। 2017 की दूसरी छमाही से शीर्षस्तरीय बैठकों की आवृत्ति बढ़ गई है।

जापान-चीन संबंधों में बड़ी सफलता तब मिली जब 14-15 मई, 2017 को जापान ने बीजिंग में पहले बेल्ट एंड रोड फोरम में हिस्सा लिया। जापानी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी) के महासचिव तोशीहिरो निकाई ने किया। फोरम में भाग लेने के अलावा, श्री निकाई ने राष्ट्रपति शी के साथ एक बैठक भी की। बैठक के दौरान , उन्होंने प्रधानमंत्री आबे का एक व्यक्तिगत पत्र सौंपा।

बीजिंग के साथ टोक्यो के संबंधों को सुधारने में प्रधानमंत्री आबे का उत्साह तब और प्रतिबिंबित हुआ जब उन्होंने 5 जून, 2017 को अपने एक भाषण में कहा , "जापान बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए तैयार है।"[17] उन्होंने कहा कि "वन बेल्ट, वन रोड इनिशिएटिव पूर्व और पश्चिम को जोड़ने के साथ-साथ दोनों के बीच के विविध क्षेत्रों को भी जोड़ने की क्षमता रखता है।" हालाँकि, प्रधानमंत्री आबे ने जापानी सहयोग के लिए तीन मापदंड रखे। पहला, "बुनियादी ढाँचा को सभी के उपयोग के लिए खुला रखना महत्वपूर्ण है, और इसे पारदर्शी एवं निष्पक्ष खरीद के माध्यम से विकसित किया जाना चाहिए।" दूसरा, परियोजनाओं को “आर्थिक तौर पर व्यावहारिक” होना चाहिए। और अंत में, परियोजनाओं का वित्तपोषण "ऋण द्वारा हो जिसे चुकाया जा सकता है" और जिससे “कर्जदार राष्ट्र की वित्तीय शांति को नुकसान नहीं पहुंचे।“ उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें उम्मीद है कि "वन बेल्ट वन रोड इनिसिएटिव” एक समान सोच वाले सामान्य ढांचे को पूरी तरह से शामिल करेगा, और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष ट्रांस-पैसिफिक आर्थिक क्षेत्र के साथ सामंजस्य स्थापित करेंगा"।

8 जुलाई, 2017 को हैम्बर्ग जी20 शिखर सम्मेलन के मौके पर , प्रधानमंत्री आबे ने राष्ट्रपति शी के साथ अपनी चौथी शिखर बैठक की, जहां दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच "स्थायी संबंध" के महत्व को दृढ़ता से स्वीकार किया। उन्होंने "जिम्मेदारी और मिशन की भावना रखने" की आवश्यकता को भी पहचाना और इस दृष्टिकोण को साझा किया कि भले ही दोनों देशों के बीच विभिन्न राजनीतिक चुनौतियां हों, लेकिन यह द्विपक्षीय संबंधों के अन्य आयामों में बाधा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि "अर्थव्यवस्था को विशुद्ध रूप से आर्थिक मुद्दे के रूप में निपटाया जाना चाहिए और लोगों से लोगों के बीच आदान-प्रदान को बढ़ाया जाना चाहिए।"[18] बैठक के दौरान, आबे ने "वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव" की व्याख्या "संभावनाओं से भरी दृष्टि" के रूप में की और सहयोग करने की अपनी इच्छा को दोहराया।[19]

मित्रता का रुख दिखाते हुए , प्रधानमंत्री आबे ने टोक्यो में चीनी दूतावास में 28 सितंबर, 2017 को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ़ चीन की स्थापना की 68वीं वर्षगाँठ तथा चीन और जापान के बीच राजनयिक संबंधों के सामान्य होने की 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक समारोह में भाग लिया। प्रधानमंत्री आबे पिछले 15 वर्षों में इस तरह के समारोह में भाग लेने वाले पहले जापानी नेता थे। [20] सामान्यीकरण की 45 वीं वर्षगांठ के अवसर पर, प्रधानमंत्री आबे और प्रीमियर ली ने बधाई संदेशों का आदान-प्रदान भी किया, जो पिछले एक दशक में उच्चस्तरीय नेताओं के बीच कभी नहीं हुआ था ।[21]

द्विपक्षीय संबंध को एक अलग स्तर पर ले जाने के प्रयास में, प्रधानमंत्री आबे ने 4 दिसंबर, 2017 को अपने भाषण में जापानी और चीनी निजी कंपनियों द्वारा किसी तीसरे देश में संयुक्त व्यापार परियोजनाओं को शुरू करने के विचार को बढ़ावा दिया। प्रधानमंत्री आबे ने कहा कि राष्ट्रपति शी और प्रीमियर ली के साथ इस मामले पर उनकी "साझा समझ" है। उन्होंने कहा कि "मुक्त और खुले भारत-प्रशांत रणनीति के तहत, जापान चीन के साथ महत्वपूर्ण सहयोग कर सकता है जिसने वन बेल्ट, वन रोड पहल को आगे बढ़ाया है।"[22]

इस दिशा में, जापानी सरकार ने बीआरआई के भीतर निजी क्षेत्र की साझेदारी को आर्थिक रूप से समर्थन देने के अपने इरादे का संकेत दिया। जापानी प्रस्ताव वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए है, जैसे कि सरकार समर्थित वित्तीय संस्थानों के माध्यम से ऋण प्रदान करना। जापानी सरकार ने "हरित" क्षेत्र, औद्योगिक आधुनिकीकरण और सैन्य क्षेत्रों की पहचान साझेदारी के क्षेत्रों के रूप में की है। "हरित क्षेत्र" में, सौर और पवन सहित वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के उत्पादन और स्वच्छ कोयला बिजली प्रौद्योगिकी के उत्पादन पर ध्यान दिया गया है। औद्योगिक पार्क और पावर ग्रिड को उन्नत करना औद्योगिक आधुनिकीकरण परियोजनाओं के केंद्र में है। सैन्य रसद के मामले में, चीन और यूरोप के बीच परिवहन गलियारे में संयुक्त परियोजनाओं की पहचान सहयोग के एक आशाजनक क्षेत्र के रूप में की गई है।[23]

बीआरआई के प्रति जापानी सरकार का बदला हुआ दृष्टिकोण इन परियोजनाओं में मौजूद व्यावसायिक अवसरों के दोहन में जापानी कंपनियों की बढ़ती रुचि का संकेत है। जुलाई 2017 में, जापानी व्यापार लॉबी, चीन में जापानी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने सदस्य कंपनियों के बीच जानकारी साझा करने के उद्देश्य से बीजिंग में एक संपर्क कार्यालय स्थापित किया।[24] अगस्त 2017 में जापानी सैन्य कंपनी, निप्पॉन एक्सप्रेस ने कजाखस्तान की राष्ट्रीय रेलवे कंपनी टेमीज़हॉली के साथ मिलकर मध्य एशिया और यूरोप से होकर चीन के पूर्वी तट से माल का परिवहन किया।[25]

जापानी व्यापार ने भी चीन से दूर जाने के कई वर्षों के बाद हाल ही में व्यापार करने में नए सिरे से रुचि दिखाई है। 2011 में चीन में जापानी एफडीआई 12.6 बिलियन डॉलर और 2012 में 13.4 बिलियन डॉलर था। 2013 में यह घटकर 9.1 बिलियन डॉलर और 2016 में 8.6 बिलियन डॉलर हो गया।[26] "चीन जोखिम" में योगदान देने वाला एक प्रमुख कारक राजनीतिक था। श्रम लागत में वृद्धि के कारण उच्च उत्पादन लागत और चीनी अर्थव्यवस्था में मंदी सहित अन्य कारकों ने "दुनिया के कारखाने" के रूप में चीन के आकर्षण को कम कर दिया।[27]

व्यवसायिक रुचि में नई दिलचस्पी चीनी बाजार में एक नई प्रवृत्ति को भुनाने के लिए भी प्रेरित करती है जो बढ़ती आय के साथ चीनी उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति में वृद्धि एवं उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों की बढ़ती मांग है। 'जापान बाहरी व्यापार संगठन' द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में पाया गया कि चीन में काम कर रहीं 40 प्रतिशत जापानी कंपनियों ने अगले एक या दो वर्षों में विस्तार करने की योजना बनाई, 2015 में इसी तरह के सर्वेक्षण से 2 प्रतिशत अंक और तीन वर्षों में पहली वृद्धि हुई।[28] 2016 में, चीन में लगभग 32, 313 जापानी फर्में चल रही थीं। नवंबर 2017 में जापानी व्यवसायियों के 250 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की बीजिंग यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों में

सुधार का संकेत है। प्रतिनिधिमंडल पिछले दो वर्षों में अपनी तरह का पहला और अब तक का सबसे बड़ा दल था।

निष्कर्ष

जैसा कि प्रधानमंत्री आबे ने 4 दिसंबर, 2017 को बताया, जापान-चीन संबंधों की वास्तविकता "अविभाज्य" है। यह एक ऐसा संबंध है जो उच्च स्तर की आर्थिक निर्भरता को प्रदर्शित कर ता है। हालांकि, इसे भरोसे की कमी, क्षेत्रों को लेकर विवाद तथा इतिहास की व्याख्या के कारण तोडा-मरोड़ा गया है। इसे एशियाई नेतृत्व में प्रतिस्पर्धा तथा राजनयिक प्रभाव के तौर पर भी जाना जाता है। यह एक तथ्य है कि "चीन का उदय" जापान के लिए सुरक्षा संबंधी और कूटनीतिक चुनौतियों को उत्पन्न करता रहेगा, फिर भी यह आर्थिक अवसरों का लाभ उठाने से टोक्यो को दूर नहीं रख सकेगा। जापान का दृष्टिकोण "चीन के उदय" को संभालना है और आंतरिक तथा बाह्य संतुलन को शामिल करते हुए एक प्रतिरोधी रणनीति के द्वारा इसके नकारात्मक परिणामों को कम करना, चीन के साथ जुड़ना और अन्य देशों के साथ साझेदारी करना है।

पूरे मामले से जुड़ी उच्च स्तर की संवेदना को देखते हुए, जापान-चीन संबंधों पर घरेलू स्तर पर होने वाली राजनीतिक उलटफेर का भी प्रभाव है । इन सभी कारकों और उनकी भौगोलिक एवं सांस्कृतिक निकटता को ध्यान में रखते हुए , जापान-चीन संबंधों की कथा बहुआयामी होगी , जिसमें एपिसोडिक गर्मी, शीतलता और संघर्ष के चरण होंगे।

हालिया रुझान से पता चलता है कि जापान-चीन संबंध एक खुशनुमा दौर में प्रवेश कर रहा है। नवंबर में चुनाव में जीत के बाद, नए आबे प्रशासन ने जापानी अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने को अपनी पहली प्राथमिकता माना है। जापान की घरेलू राजनीति में अपनी मजबूत स्थिति को देखते हुए, प्रधानमंत्री आबे चीन के साथ सहयोग बढाने में राजनीतिक पूँजी लगाने के लिए अधिक विवश नहीं हैं। बीआरआई में व्यापार का अवसर विशेष रूप से आबे के पक्ष में एक तार्किक कदम होगा खासकर तब जब ट्रांस-पैसिफिक पार्टनरशिप (टीपीपी) को अमल में नहीं लाया जा सकेगा। आबे की आर्थिक रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा (जिसे अबेनॉमिक्स कहा जाता है) विदेशी बाजारों तक पहुँच को बढ़ाने पर जोर देता है ताकि गतिहीन हो चुकी जापानी अर्थव्यवस्था में जान फूंकी जा सके।

जापान-चीन संबंध को बाधित करने वाली एक महत्वपूर्ण समस्या दोनों देशों के नेताओं के बीच विश्वास की कमी थी। चीन में एक नए नेतृत्व के उद्भव से इस अंतर को कम करने में मदद मिल सकती है। बाह्य व्यापार के उप प्रीमियर, वांग यांग का चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के राजनीतिक ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी की चौथी रैंकिंग के सदस्य के तौर पर पदोन्नति तथा पोलित ब्यूरो के सदस्य के रूप में स्टेट काउंसलर यांग जिएची की पदोन्नति को जापान में सकारात्मक रूप से देखा जा रहा है।[29]

वाइस प्रीमियर वांग, एक प्रतिबद्ध आर्थिक सुधारक, को जापान के साथ मजबूत संबंध रखने के लिए जाना जाता है। बीजिंग के शीर्ष राजनयिक पार्षद यांग, 2012 के बाद के परिदृश्य में बैठकों में शीर्ष नेतृत्व की अनुपस्थिति में जापान- चीन संबंधों के लिए काम करने वाले मुख्य व्य क्ति थे।

यांग के जापा न के साथ मजबूत संबंध भी हैं। पिछले पंद्रह वर्षों में बीजिंग में पोलित ब्यूरो में पदोन्नति पाने वाले पहले शीर्ष राजनयिक अधिकारी यांग की पदोन्नति पर, जापान के विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा: "यांग ने जापान और चीन के बीच संबंधों को बेहतर बनाने के लिए अत्यधिक प्रयास किए हैं।"[30]

****

** डॉ.जोजिन वी जॉन, रिसर्च फेलो, आईसीडब्ल्यूए, वैश्विक मामलों की भारतीय परिषद, नई दिल्ली।*
अस्वीकरण: व्यक्त किए गए विचार शोधकर्ता के हैं, परिषद के नहीं।

अंत टिप्पण

1 "Abe hails 'fresh start' to Japan-China ties after Xi meeting", The Reuters, November 12, 2017, https://www.reuters.com/article/us-apec-summit-japan-china/abe-hails-fresh-start-to-japan-china-ties-after-xi-meeting-idUSKBN1DBoHU (Accessed on November 23, 2017)
2 "Japan-China Summit Meeting", The Ministry of Foreign Affairs, Japan November 11, 2017, http://www.mofa.go.jp/a_o/c_m1/cn/page4e_000711.html (Accessed on November 23, 2017)
3"Abe, Li hail improved Japan-China ties, commit to do more", Nikkei Asia Review, November 14, 2017, https://asia.nikkei.com/Politics-Economy/International-Relations/Abe-Li-hail-improved-Japan-China-ties-commit-to-do-more (Accessed on November 23, 2017)
4"Japan-China Summit Meeting", The Ministry of Foreign Affairs, Japan November 13, 2017, http://www.mofa.go.jp/a_o/c_m1/cn/press3e_000119.html (Accessed on November 23, 2017)
5 "Japan, China to set up contact system to avoid sea, air clashes", Kyodo News, December 6, 2017, https://english.kyodonews.net/news/2017/12/4193b335fc6e-urgent-japan-china-to-set-up-contact-system-to-avoid-sea-air-clashes.html (Accessed on December 10, 2017)
6"Japan, China to set up contact system to avoid sea, air clashes", The Kyodo News, December 6, 2017, https://english.kyodonews.net/news/2017/12/4193b335fc6e-urgent-japan-china-to-set-up-contact-system-to-avoid-sea-air-clashes.html (Accessed on December 17, 2017)
7Tetso Kotani, "The East China Sea: Chinese Efforts to Establish a "New Normal" and Prospects for Peaceful Management", Maritime Issue, July 18, 2017, http://www.maritimeissues.com/politics/the-east-china-sea-chinese-efforts-to-establish-a-new-normal-and-prospects-for-peaceful-management.html (Accessed on December 17, 2017)
8"At Tokyo meeting, Japan urges China to be more transparent about military plans", The Japan Times, October 28, 2017, https://www.japantimes.co.jp/news/2017/10/28/national/politics-diplomacy/tokyo-meet-japan-urges-china-become-transparent-military-plans/#.Whav7UqWaM9
9 "Japan-China Summit Meeting", The Ministry of Foreign Affairs, Japan November 11, 2017, http://www.mofa.go.jp/a_o/c_m1/cn/page4e_000711.html (Accessed on November 23, 2017)
10 "Xi Jinping Meets with Prime Minister Shinzo Abe of Japan", Ministry of Foreign Affairs, PRC, November 11, 2017, http://www.fmprc.gov.cn/ce/ceindo/eng/xwdt/t1510293.htm (Accessed on November 25, 2017)
11 "Japan-China Summit Meeting", The Ministry of Foreign Affairs, Japan November 11, 2017, http://www.mofa.go.jp/a_o/c_m1/cn/page4e_000711.html (Accessed on November 23, 2017)
12"Welcome Reception for the Third Japan-China Business Leader and Former High-Level Government Official Dialogue ", Kantei, December 4, 2017, https://japan.kantei.go.jp/98_abe/actions/201712/4article4.html (Accessed on December 7, 2017)
13"Reciprocal visits by Japan, China leaders vital for regional stability", The Yomiuri Shimbun, November 14, 2017, http://the-japan-news.com/news/article/0004066599 (Accessed on November 23, 2017)
14"Japan, China must work closer to improve stability in Asia", The Asahi Shimbun, November 14, 2017, http://www.asahi.com/ajw/articles/AJ201711140020.html (Accessed on November 23, 2017)
15"Reciprocal visits by Japan, China leaders vital for regional stability", The Yomiuri Shimbun, November 14, 2017, http://the-japan-news.com/news/article/0004066599 (Accessed on November 23, 2017)

16"Abe needs to seize opportunity to push for a thaw ", The Global Times, November 16, 2017, http://www.globaltimes.cn/content/1075674.shtml (Accessed on November 23, 2017)
17http://japan.kantei.go.jp/97_abe/statement/201706/1222768_11579.html
18"Japan-China Summit Meeting", Ministry of Foreign Affairs of Japan, July 8, 2017, http://www.mofa.go.jp/a_o/c_m1/cn/page4e_000636.html (Accessed on November 27, 2017)
19Abe, Xi in accord on trade project but differ over North Korea", The Asahi Shimbun, July 9, 2017, http://www.asahi.com/ajw/articles/AJ201707090013.html (Accessed on November 23, 2017)
20 "Abe joins gala by Chinese Embassy", China Daily, September 29, 2017, http://www.chinadaily.com.cn/world/2017-09/29/content_32626783.htm (Accessed on November 23, 2017)
21 "China and Japan revive goodwill gesture to mark diplomatic milestone", South China Morning Post, September 29, 2017, http://www.scmp.com/news/china/diplomacy-defence/article/2113437/china-and-japan-revive-goodwill-gestures-mark(Accessed on November 23, 2017)
22 "Welcome Reception for the Third Japan-China Business Leader and Former High-Level Government Official Dialogue ", Kantei, December 4, 2017, https://japan.kantei.go.jp/98_abe/actions/201712/4article4.html (Accessed on December 7, 2017)
23 "Japan to help finance China's Belt and Road projects", Nikkei Asia Review, December 6, 2017, https://asia.nikkei.com/Politics-Economy/International-Relations/Japan-to-help-finance-China-s-Belt-and-Road-projects (Accessed on December 7, 2017)
24 Nippon Express climbs aboard China's Belt and Road Initiative", Nikkei Asian Review, September 30, 2017, https://asia.nikkei.com/Business/Companies/Nippon-Express-climbs-aboard-China-s-Belt-and-Road-Initiative (Accessed on December 7, 2017)
25 Ibid
26 "Japanese Trade and Investment Statistics", https://www.jetro.go.jp/en/reports/statistics/ (Accessed on December 7, 2017)
27 Rumi Aoyama, "Getting down to business on Japan–China relations", East Asia Forum, August 21, 2017 http://www.eastasiaforum.org/2017/08/21/getting-down-to-business-on-japan-china-relations/ (Accessed on December 7, 2017)
28 "Japan Inc. showing renewed interest in China investment", Nikkei Asian Review, May 12, 2017, https://asia.nikkei.com/Business/Trends/Japan-Inc.-showing-renewed-interest-in-China-investment (Accessed on December 7, 2017)
29 "New Japan-friendly member of China's top political panel raises hopes for warmer ties", Japan Times, November 2, 2017, https://www.japantimes.co.jp/news/2017/11/02/national/politics-diplomacy/new-japan-friendly-member-chinas-top-political-panel-raises-hopes-warmer-ties/#.WkSYgze_PIU (Accessed on December 7, 2017)
30 "Japan looks to China's Yang as Abe-Xi relations remain frosty", Asahi Shimbun, October 26, 2017, http://www.asahi.com/ajw/articles/AJ201710260047.html (Accessed on December 17, 2017)